मैरी एंजेल और अन्य

बनाम

तमिलनाडु राज्य 13 मई 1999

[के.टी. थॉमस और एम.बी. शाह, जे.जे.]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 482- उच्च न्यायालय की अंर्तनिहित शक्तियां- व्यय लगाने की शक्ति- व्यय लगाने की शक्ति का दायरा-मैक्सिम-मैक्सिम-एक्सप्रेसियो यूनिअस एक्सक्लूसिव की प्रयोज्यता है।

1 से 6 के खिलाफ धारा 498 ए, 406, 420, 315 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। भारतीय दंड संहिता एवं एस.एस. दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4। A3 से 6, अपीलकर्ताओं को सत्र न्यायालय ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि वे दहेज की मांग नहीं की थी और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री भी नहीं थी उनके कहने पर गर्भपात की दवा दी गई। संशोधन में शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने आरोपमुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया और उस आदेश के अनुसरण में, सत्र न्यायाधीश ने खिलाफ आरोप तय किये अपीलकर्ता भी. अपीलकर्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए

आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं था, आरोप तय न करने के आदेश के खिलाफ उस संशोधन का खुलासा किए बिना उच्च न्यायालय द्वारा पहले यह कहते हुए अनुमति दी गई थी कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी यह देखते हुए कि कार्यवाही 8 वर्षों तक खींची गई थी और अपीलकर्ताओं ने सत्र न्यायालय को इसका अनुपालन करने की अनुमति नहीं दी थी उच्च न्यायालय ने मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है संभव, रुपये की व्यय लगाई. प्रत्येक अपीलकर्ता को 10,000 रुपये का भुगतान किया जाना है शिकायतकर्ता, 1 की पत्नी को। यह अपील चुनौती देते हुए दायर की गई थी उच्च न्यायालय का उक्त आदेश।

अपीलकर्ताओं ने कहा कि आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के पास नहीं है धारा 148(3), 342 और 359 के तहत दिए गए प्रावधानों को छोड़कर व्यय लगाने का क्षेत्राधिकार नहीं है एवं ये धाराएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता उच्च न्यायालय को जुर्माना लगाने का अधिकार देती है न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग उक्त के विपरीत नहीं किया जा सकता है।

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि धारा के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता के 482 में, उच्च न्यायालय के पास

लागत लगाने का अंतर्निहित क्षेत्राधिकार है। कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए और इस मामले में उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार का सही प्रयोग किया। अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र और क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने वाली पत्नी को भुगतान की जाने वाली अधिरोपित व्यय को यह मानते हुए कि अभियुक्त ने सत्र न्यायालय को मामले के साथ आगे बढ़ने से रोका और उच्च द्वारा पारित पिछले आदेश को दबा कर कोर्ट ने आरोपों को रद्द करने और खारिज करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उनके खिलाफ फंसाया गया।

इस न्यायालय के विचारार्थ उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या उच्च न्यायालय के पास अपने निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए व्यय लगाने का ऐसा अधिकार क्षेत्र था।

इस न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।

निर्धारणः1.1 धा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, न्यायालय के पास ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति है (किसी भी प्रावधान के साथ असंगत नहीं)। उचित मामलों में व्यय के लिए आदेश सहित, (i) संहिता के तहत पारित किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए या (iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्य को

सुरक्षित करने के लिए। यह असाधारण शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। लागत मुकदमेबाजी के खर्चों को पूरा करने के लिए हो सकती है या उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकरणीय हो सकती है। [609-D]

1.2 धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता संहिता के अन्य प्रावधानों से स्वतंत्र है और यह स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाता है। इसलिए, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए, उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार है जिसमें सूचना देने वाले (शिकायतकर्ता) को व्यय का भुगतान करने का आदेश शामिल हो सकता है और अनुभाग की भाषा में कोई बंधन नहीं है। यह शक्ति नहीं है किसी अन्य धारा द्वारा नियंत्रित किया जाता है और न ही किसी ऐसे प्रावधान से कम किया जाता है जो अदालत को व्यय तय करने का अधिकार देता है। यह क्षेत्राधिकार असाधारण प्रकृति का है और इसे प्राप्त करने के लिए असाधारण मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए जो अनुभाग में बताया गया उद्देश्य है। दूसरे लागत अनुभाग में बताए गए उद्देश्य के लिए हो सकती है। दूसरे, लागत किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकती है मुकदमेबाजी के खर्चों को पूरा करना, क्योंकि यह अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को

रोकने या न्याय सुनिश्चित करने या संहिता के तहत पारित किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए अनुकरणीय हो सकता है। [600-B-E-]

1.3 ऐसा कोई विपरित प्रावधान नहीं है कि उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत व्यय प्रदान की जा सकती है, उच्च न्यायालय व्यय देने के अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसे मामलों में जहां कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या न्याय सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय को लगता है कि अनुकरणीय व्यय सहित लागतों के लिए आदेश पारित करना आवश्यक है, तो वाक्यांश "ऐसे आदेश" में वही शामिल है और इसे प्रतिबंधित करने का कोई कारण नहीं है। ऐसी शक्ति वाक्यांश का दायरा. दूसरी बात के संबंध में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार क़ानून यह नहीं कहता कि अंतर्निहित शक्ति को मान्यता दी गई है। [606-E-F]

1.4 कहावत "एक्सप्रेसियो यूनिस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरियस" का इसका सीमित संचालन है। इसका संचालन उन अनुभागों के संबंध में प्रतिबंधित किया जाना है जो अदालत को कुछ मामलों में व्यय अनुदान देने का अधिकार यह मानते हुए दिया गया है कि उन धाराओं में उल्लिखित मामलों के लिए, अदालत व्यय देने के अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती है या व्यय देने का आदेश पारित नहीं कर सकती है और तरीके उक्त अनुभागों द्वारा प्रदान किए गए हैं से

भिन्न है। इस कहावत से असंगतता और अन्याय को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि मामलों में जहां न्यायालय ने पाया कि धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कुछ गुप्त उद्देश्यों के लिए एक अनुचित याचिका है, जिसमें शामिल हैं न्यायालय की कार्यवाही को खींचते हुए यह कोई अन्य आदेश पारित कर सकता है, लेकिन व्यय के लिए आदेश नहीं। प्रक्रिया से संबंधित कोई भी विधायी अधिनियम नहीं हो सकता। सभी मामलों के लिए प्रावधान करें और न्यायालय के पास कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा अंतर्निहित शक्तियां होनी चाहिए जो उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हैं कर्तव्यों का धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की व्याख्या के लिए उपरोक्त कहावत का अनुप्रयोग। केवल सीमित संचालन होगा। [607-F-G; 609-C]

पम्पथी बनाम मैसूर राज्य, (1966) सप्ल एससीआर 477; डॉ. रघुबीर शरण बनाम बिहार राज्य, (1966) 2 एससीआर 336; सहायक कलेक्टर सेंट्रल एक्साइज बनाम नेशनल टोबैको कंपनी, [1972} 2 एससीसी 560; प्रभानी परिवहन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड बनाम आरटीए औरंगाबाद, (1960) 3 एससीआर 177; हरीश चंद्र वाजपेई बनाम त्रिलोकी सिंह, [1957) एससीआर 371 और बिहार राज्य बनाम राम चंदर अग्रवाल, [1979) आई एससीआर 1एल4, पर भरोसा किया

लासु जानू पवार और अन्य। वी सम्राट, (1948) आकाशवाणी जन्म 169; पर। शंकर लिंगा मुदलियार बनाम नारायण मुदलियार और अन्य, {1922) एआईआर मैड 502 और पी. वीरप्पा बनाम। अवुदायम्मल एवं अन्य, आकाशवाणी (1925) मैड 438, प्रतिष्ठित।

रे बॉम्बे सिविल फंड एक्ट. 1882; प्रिंगल बनाम सीक्रेटजी1 वाई ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, (1889) चांसरी डिवीजन 288; वेस्ट हैम यूनियन बनाम चर्च के संरक्षक वार्डन और ओवरसीज एवं अन्य, (1896) कानून रिपोर्ट 477; डीन बनाम विसेनग्रंड,(1955) 2 क्यूबीडी 120 और कोलक्हून बनाम ब्रूक्स, 1887 (19) क्यूबीडी 400, संदर्भित।

आपराधिक अपील.ए. ते क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या.

1999/570

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.7.98 से।

आर.सी.नं. 1996 का 601

अपीलकर्ताओं के लिए एस. शिवसुब्रमण्यम और आर. अय्याम पेरुमल

वी.जी. नंबर । में प्रतिवादी के लिए प्रगासम

के.एस. प्रतिवादी नंबर 2 के लिए ज्ञानसंबंदन और एम.ए. चिन्नासामी।
न्यायालय का निर्णय शाह , जे द्वारा सुनाया गया। छुट्टी दी गई।

इस अपील में यह सवाल शामिल है कि क्या उच्च न्यायालय के पास ".Rs.10000 की अनुकरणीय व्यय" लगाने का अधिकार क्षेत्र है। धारा के तहत परेशान करने वाली याचिका को खारिज करते समय प्रत्येक अपीलकर्ता को 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत लगाए गए आरोप को खारिज करने के लिए अपीलकर्ता है?

29 सितंबर, 989 को जोसेफिन जया द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि उसके ससुराल वालों ने उसके पिता से रुपये की मांग की थी। 60,000 नकद, दुल्हन के लिए 65 सोने के गहने और दूल्हे के लिए नौ सोने के गहने या इसी तरह के गहने; कि 60,000 रुपये में से रु. 50,000 का भुगतान किया गया; कि शादी के बाद उसके साथ क्रूर व्यवहार किया गया और एक रंगीन टेलीविजन और रुपये की गैरकानूनी मांग की गई। 50,000 नकद. यह भी आरोप है कि ससुराल वालों की शह पर आरोपी बनाया गया। संख्या 2 से 6, आरोपी नंबर । (उसके पति) ने उसके गर्भ को गिराने के उद्देश्य से कुछ दवाएँ दीं। प्रारंभिक जांच के बाद 18 अक्टूबर को मो. 1989, धारा 498 (ए), 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत ए 1 से ए 6 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। 420, 315 आई.पी.सी. और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4। मामला था। सत्र न्यायालय, नागरकोइल को प्रतिबद्ध किया

गया था और इसे 1989 के सत्र मामले संख्या 10 के रूप में क्रमांकित किया गया था। अभियुक्त संख्या 3 से 6 ने अपने आरोपमुक्त करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत एक आवेदन दायर किया था।

13 जून, 1996 के उस आदेश के विरुद्ध, आरोपी संख्या 3 से 6 तक, यानी वर्तमान अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 के आपराधिक पुनरीक्षण मामले संख्या 601 को इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं था। उनके खिलाफ आरोप तय करना. कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कार्यवाही 8 साल तक चली और याचिका दायर की गई विद्वान वकील को भी यह बताए बिना कि पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध है आरोप तय न करने की अनुमति पहले उच्च न्यायालय ने यह कहकर दी थी कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। न्यायालय ने यह भी देखा कि उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय को यथाशीघ्र सुनवाई पूरी करने के निर्देश के बावजूद अपीलकर्ताओं ने सत्र की अनुमति नहीं दी है। न्यायालय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों का अनुपालन करेगा। विचार उपरोक्त आचरण पर, उच्च न्यायालय ने रुपये की लागत लगाई। अपीलकर्ताओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपये का भुगतान मुखबिर (शिकायतकर्ता), आरोपी संख्या की पत्नी को किया जाएगा। 1 और सत्र न्यायालय को आदेश की संसूचना की तारीख से दो महीने के भीतर

मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया। इस अपील में हमारे सामने उस आदेश को चुनौती दी गयी है।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय को प्रावधान के अलावा व्यय लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है सीआरपीसी की धारा 148(3), 342 और 359 के तहत। न्यायालय को सशक्त बनाना, लागत लगाना और प्रस्तुत करना कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ नहीं हो सकतीं उक्त प्रावधानों के विपरीत प्रयोग किया गया। इसके विपरीत, विद्वान वकील प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय ने अंतर्निहित किया है कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यय लगाने का अधिकार क्षेत्र या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक या दूसरे के लिए कारण, अभियुक्त ने सत्र न्यायालय को मामले में आगे बढ़ने से रोका और उच्च न्यायालय द्वारा पारित पिछले आदेश को दबा दिया। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया और क्रूर व्यवहार करने वाली पत्नी (सूचनाकर्ता) को भुगतान की जाने वाला व्याय लगाया।

माना कि क्रिमिनल आर.सी. संख्या 442 of 1990 और 1990 की आपराधिक आरपी संख्या 440, of 1990 उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत निर्णय और आदेश दिनांक 9 जुलाई 1993 द्वारा, उक्त पर्याप्त पुनरीक्षण याचिकाओं को यह मानते हुए अनुमति दी कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर आधार आरोप तय करते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कानून में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया और साथ ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अपीलकर्ताओं को रिहा करना। उक्त आदेश के बावजूद भी दमन कर वही, अपीलकर्ताओं ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिका दायर की। ऐसी परिस्थितियों में, अदालत ने इसे रोकने के लिए आरोपी नंबर 1 की पत्नी को भुगतान की जाने वाली व्यय लगाई है न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करना।

प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय के पास निर्णय लेने के लिए ऐसा क्षेत्राधिकार था? हम सबसे पहले आपराधिक प्रक्रिया की प्रासंगिक धाराओं का उल्लेख करेंगे सीआर.पी.सी. जिस पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है जो न्यायालय को व्यय लगाने का अधिकार देता है। धारा 148(3) यह प्रावधान करती है जब किसी कार्यवाही में किसी भी

पक्ष द्वारा कोई व्यय लगाई गई हो धारा 145, धारा 146 या धारा 147, मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाता है यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी व्यय का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा, चाहे ऐसी पार्टी द्वारा या उसके द्वारा कार्यवाही में कोई अन्य पक्ष, और चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से या अनुपात और ऐसी लागतों में इसके संबंध में किया गया कोई भी खर्च शामिल हो सकता है गवाहों और वकील की फीस, जिसे न्यायालय उचित मान सकता है। धारा 342 सीआर.पी.सी में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किसी आवेदन पर विचार कर सकता है धारा 340 के तहत शिकायत दर्ज करने या धारा 341 के तहत अपील दायर करने के लिए, लागत के संबंध में ऐसा आदेश देने की शक्ति होगी जो उचित हो। आगे धारा 359 न्यायालय को शिकायतकर्ता को व्यय का भुगतान करने का आदेश देने का अधिकार देती है गैर संज्ञेय मामले में, यदि यह अभियुक्त को दोषी ठहराता है और ऐसे मामले में, न्यायालय शिकायतकर्ता द्वारा किए गए खर्च के भुगतान के लिए आदेश पारित कर सकता है मामले का अभियोजन और ऐसी लागतों में कोई भी खर्च शामिल हो सकता है प्रक्रिया शुल्क, गवाहों और वकील की फीस के संबंध में जो न्यायालय उचित मानता है. इस शक्ति का प्रयोग अपीलीय द्वारा भी किया जा सकता है न्यायालय या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की अपनी शक्ति का प्रयोग अपील या पुनरीक्षण. धारा 357 सीआर.पी.सी. मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करती है अपराध के कारण

हुई चोट या मृत्यु की स्थिति में किसी भी नुकसान के लिए पीड़ित पीड़ितों के उत्तराधिकारियों को लगाए गए जुर्माने से बाहर करें और पुरस्कृत करते हुए मुआवजा अदालत को अन्य बातों के साथ-साथ खर्चों पर भी विचार करना होगा अभियोजन में उचित रूप से खर्च किया गया; धारा 358 सीआर.पी.सी के भुगतान का प्रावधान है कि मुआवजा जहां कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी को किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार के बिना गिरफ्तार करने का कारण बनता है, तो मुआवजा मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम रु.100 का पुरस्कार दिया जा सकता है। यह इसलिए है, प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय को कॉस्ट डे होर्स का आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है उपरोक्त वैधानिक प्रावधान।

हमारे विचार में धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता दूसरे से स्वतंत्र खड़ा है। संहिता के प्रावधान और यह स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाता है। न्यायालय ने यह प्रावधान करते हुए कहा कि "इस संहिता में कुछ भी ऐसे आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।" इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने या इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है। न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया या अन्यथा। इसलिए, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा अपने हितों को सुरक्षित

करने के लिए न्याय की दृष्टि से, उच्च न्यायालय को "ऐसा आदेश" पारित करने का अधिकार है जो हो सकता है इसमें मुखबिर (शिकायतकर्ता) और भाषा को व्यय का भुगतान करने का आदेश शामिल है इस धारा में कोई बंधन नहीं रखा गया है। यह शक्ति वातानुकूलित नहीं है या किसी अन्य अनुभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है और न ही किसी प्रावधान द्वारा कम किया जाता है अदालत को व्यय तय करने का अधिकार देना। इसमें कोई शक नहीं, यह अधिकार क्षेत्र. असाधारण प्रकृति का है और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए असाधारण मामलों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए अनुभाग में कहा गया है. दूसरे, लागत किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकती है मुकदमेबाजी के खर्चों को वहन करना क्योंकि इसे रोकने के लिए यह अनुकरणीय हो सकता है न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग या न्याय सुनिश्चित करने या उसे प्रभावी बनाने के लिए संहिता के तहत पारित किसी भी आदेश के लिए।

विद्वान वकील अपीलकर्ताओं ने इसके निर्णय पर भरोसा किया उड़ीसा राज्य बनाम राम चंदर अग्रवाल आदि में न्यायालय, [1979] 1 एससीआर 1114 और प्रस्तुत किया कि जब आपराधिक प्रक्रिया संहिता पुरस्कार देने का प्रावधान करती है तो उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग व्ययों का पुरस्कार देने के लिए नहीं किया जा सकता है। सीमित मामलों में लागत. उपरोक्त मामले में, न्यायालय विचार कर रहा था विवाद:

क्या उच्च न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 369 के तहत विशिष्ट रोक के बावजूद अपने निर्णय और आदेश की समीक्षा कर सकता है लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के अलावा। कोर्ट ने धारा 369 के मद्देनजर यह माना करोड़। सीआर. पी.सी. जो सभी अदालतों को तब प्रतिबंधित करता है जब उसने अपने फैसले में बदलाव के लिए हस्ताक्षर कर दिए हों या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के अलावा उसकी समीक्षा करें और उच्च न्यायालय के मामले में, निषेध ऐसे उच्च न्यायालय का गठन करने वाले लेटर्स पेटेंट या अन्य उपकरण के अधीन था। नई संहिता के तहत समान प्रावधान धारा 362 में, अगला भाग हटा दिया गया है। इसलिए, न्यायालय ने माना कि धारा 369 का स्पष्ट अर्थ देते हुए, यह स्पष्ट था कि कोई भी न्यायालय, धारा में किए गए अपवाद के अधीन, अपने फैसले में बदलाव या समीक्षा नहीं करेगा; अंतर्निहित उच्च न्यायालय की शक्तियां किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए थीं संहिता या किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए। इसलिए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संहिता के विशिष्ट प्रावधानों के साथ असंगत होगी। कोर्ट ने आगे कहा संहिता की धारा 56एल(ए) कोई नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करती, यह केवल सुरक्षा प्रदान करती है उच्च न्यायालय के पास मौजूद मौजूदा अंतर्निहित शक्तियां आवश्यक हैं (अन्य के बीच)। उद्देश्यः न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना और "धारा की शुरूआत से, यह स्पष्ट कर दिया गया कि

न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों, के लिए अनुभाग में उल्लिखित उद्देश्यों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों द्वारा सीमित या प्रभावित नहीं माना जाएगा।"

इसके अलावा, पंपथी बनाम मैसूर राज्य के मामले में, [1966] अनुपूरक। एससीआर 477, इस न्यायालय ने इस तर्क से निपटा कि उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 56एल(ए) के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। सीआर.पी.सी., 1898 में अपील के निपटान तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 426 के तहत अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने पर जमानत रद्द कर दी गई। उक्त तर्क को अस्वीकार करते हुए, न्यायालय ने माना कि यह सच है कि धारा 498 और धारा 497(5) में, विधानमंडल ने मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा किए गए आरोपी व्यक्तियों के मामले में जमानत बांड रद्द करने का स्पष्ट प्रावधान किया था, लेकिन नहीं द्वारा ऐसा स्पष्ट प्रावधान किया गया है किसी दोषी व्यक्ति के मामले में विधानमंडल और जिसकी सज़ा हो चुकी है धारा 426 के तहत निलंबित कर दिया गया है, फिर भी अंतर्निहित अभ्यास के लिए कोई रोक नहीं है अपील लंबित रहने तक जमानत रद्द करने की शक्तियाँ। न्यायालय ने कहा, "स्पष्ट रूप से एक खामी है लेकिन विधायिका द्वारा एक विशिष्ट बात कहने की चूक है इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट रूप से चूक या असावधानी के कारण है और इसे

जानबूझकर नहीं माना जा सकता है।" न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल धारा में उल्लिखित तीन उद्देश्यों में से किसी एक के लिए ही किया जा सकता है; इसे लागू नहीं किया जा सकता है किसी के संबंध में संहिता के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा कवर किया गया मामला; यदि इसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रावधान के साथ असंगत होगा तो इसे लागू नहीं किया जा सकता है संहिता का; यदि विचाराधीन मामला संहिता के किसी विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है, तो शक्ति लागू हो जाएगी। न्यायालय ने उचित रूप से कहा, "प्रक्रिया से संबंधित कोई भी विधायी अधिनियम उन सभी मामलों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है जो संभवतः उत्पन्न हो सकते हैं और यह एक स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय के पास कानून के स्पष्ट प्रावधान के अलावा अंतर्निहित शक्तियां होनी चाहिए, जो उचित के लिए उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं।" कानून द्वारा उन पर लगाए गए कर्तव्यों का निर्वहन।"

इसके बाद, हम डॉ. रघुबीर शरण बनाम बिहार राज्य, [1964] 2 एससीआर 336 के फैसले का उल्लेख करेंगे, जिसमें इस न्यायालय ने एक चिकित्सक के खिलाफ की गई टिप्पणियों को gVkus की उच्च न्यायालय की शक्ति पर विचार किया था।

मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने तक अभियुक्त के स्वास्थ्य पर अपनी राय प्रस्तुत की। के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के दायरे पर

विचार करते हुए संहिता की धारा 561 (ए), न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का संक्षेप में विश्लेषण किया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग किया जा सकता हैः-

> "जब हम किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बात करते हैं तो हमारा मतलब उन शक्तियों से है जो राज्य में सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण नागरिक और आपराधिक तौर पर सामान्य क्षेत्राधिकार रखती हैं। राज्य में अदालतें, यहाँ उस अदालत में। एक अर्थ में शक्तियाँ उस स्थिति का एक अभिन्न गुण हैं जो वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में रखती है। ये शक्तियाँ आंशिक रूप से प्रशासनिक और आंशिक रूप से न्यायिक हैं। जब वे प्रयोग योग्य होते हैं तो वे आवश्यक रूप से न्यायिक होते हैं न्यायिक आदेश के संबंध में और न्याय के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए। जब हम न्याय के अंत की बात करते हैं तो हम इस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करते हैं इसमें न्याय की कोई अस्पष्ट या अस्पष्ट अवधारणा शामिल नहीं है, न ही यहां तक कि दार्शनिक अर्थ में न्याय, लेकिन कानून के अनुसार न्याय, क़ानून और सामान्य क़ानून. फिर, यह शक्ति नहीं है हर बार

उच्च न्यायालय को लगता है कि ऐसा न्याय का अपराध हुआ है। क्योंकि, राज्य के प्रक्रियात्मक कानून अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकांश त्रुटियों को सुधारने का प्रावधान करते हैं परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हो गया है। इन त्रुटियों को केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेकर ही ठीक किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अंतर्निहित शक्तियाँ उपलब्ध असाधारण शक्तियों की प्रकृति में हैं केवल वहां जहां उच्च न्यायालय को ऐसा करने के लिए कोई स्पष्ट शक्ति उपलब्ध नहीं है एक विशेष वस्तु और जहाँ उसकी व्यक्त शक्ति नकारात्मक न हो ऐसी अंतर्निहित शक्ति का अस्तित्व। इसके प्रयोग के लिए अतिरिक्त शर्त, जहां तक अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उनके आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले मामलों का संबंध है, यह आवश्यक होना चाहिए आपराधिक संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए इसका सहारा लेना प्रक्रिया या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए।

टिप्पणियों को हटाने की शक्ति निस्संदेह एक असाधारण शक्ति है लेकिन फिर भी यह एक प्रकार की

शिकायत के निवारण के लिए मौजूद है जिसके लिए क़ानून स्पष्ट शब्दों में कोई उपाय प्रदान नहीं करता है। यह कि क़ानून यह तथ्य मानता है कि उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं हैं और वे अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग जारी रख सकते हैं, जिससे तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक, असाधारण परिस्थितियों में असाधारण अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है शक्तियां. दूसरा, उच्च न्यायालयों के पास न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित रखने की अंतर्निहित शक्ति है। तीसरा, संहिता के स्पष्ट प्रावधान उस शक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं। सटीक शक्तियाँ जो यहाँ उच्च में निहित हैं न्यायालय को जानबूझकर अच्छे कारणों से 561-ए द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। स्पष्टतः विविधता को परिभाषित करने का प्रयास करना संभव नहीं है परिस्थितियाँ जो उनके अभ्यास की मांग करेंगी। निस्संदेह, यह खंड कोई नई शक्ति प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह करने की सामान्य शक्ति को मान्यता देता है जो कि "इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए" आवश्यक है। लेकिन

> फिर, क़ानून यह नहीं कहता कि मान्यता प्राप्त अंतर्निहित शक्ति केवल वही है जिसका प्रयोग किया गया है अतीत या तो. इसमें जो कहा गया है वह यह है कि उच्च न्यायालयों में हमेशा से ऐसा था अंतर्निहित शक्ति और यह शक्ति छीनी नहीं गई है। जब भी किसी आपराधिक मामले में विचार के लिए प्रश्न उठता है कि क्या? विशिष्ट परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के पास संहिता या अन्य क़ानून में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में एक विशेष प्रकार का आदेश देने की शक्ति है, लागू होने वाला परीक्षण यह होगा कि क्या संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए।"

उपरोक्त निर्णयों से, यह स्पष्ट है कि यदि किसी विशेष विषय वस्तु को नियंत्रित करने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान है तो इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है 'न्यायालय' की अंतर्निहित शक्तियों का आह्वान या प्रयोग करना क्योंकि न्यायालय है के प्रावधानों को निर्धारित तरीके और तरीके से लागू करना आवश्यक है क़ानून जो विशेष विषय-वस्तु को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन राज्य का सर्वोच्च न्यायालय न्याय करने केलिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है कानून के अनुसार जहां किसी

विशेष कार्य को करने के लिए कोई व्यक्त शक्ति उपलब्ध नहीं है और व्यक्त शक्ति ऐसी शक्ति के अस्तित्व को नकारात्मक नहीं करती है। यह सच है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत, लागत पुरस्कार देने के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं केवल वही हैं जो ऊपर बताए गए हैं। साथ ही, इसमें कोई विशेष बाधा नहीं है किसी अन्य मामले में, लागत प्रदान नहीं की जा सकती। इसके अलावा, गैर-संज्ञेय मामलों में, धारा 359 अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय सहित न्यायालयों को सशक्त बनाती है या सत्र न्यायालय ने पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोषी अभियुक्त को शिकायतकर्ता को व्यय का पूरा या आंशिक भुगतान करने का आदेश दिया। अभियोजन में उसके द्वारा किया गया खर्च जिसमें प्रक्रिया शुल्क, गवाहों और वकील की फीस के संबंध में किया गया खर्च शामिल है, जिस पर न्यायालय विचार कर सकता है उचित। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक संज्ञेय मामले में और अपील में या उससे उत्पन्न पुनरीक्षण के मामले में, उच्च न्यायालय अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता लागत प्रदान करने के लिए उक्त प्रावधान लागू करें। लेकिन ऐसा अनुमान नहीं है उन मामलों में संभव है जहां न्यायालय धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहा है यह कहा जाना चाहिए कि संज्ञेय मामलों में भी धारा 357 के तहत अभियुक्तों पर लगाए गए जुर्माने में से मुआवजा देते समय, अन्य बातों के अलावा, न्यायालय अभियोजन में उचित रूप से किए गए खर्चों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसलिए,

ऐसी शक्ति का प्रयोग, इसके विपरीत, में होगा अनुरूप· और सीआरपीसी की धारा 148(3), 342 और 357 या 359 के तहत प्रदत्त शक्तियों के विरोध में नहीं। उचित मामलों में, यह कहां है ऐसा आदेश पारित करने के लिए आवश्यक है, न्यायालय निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लागतें दे सकता है, अर्थात्, (i) न्यायालय के तहत पारित किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए और (iii) के अंत को सुरक्षित करने के लिए वहाँ के रूप में न्याय "ऐसी शक्ति" के प्रयोग के लिए कोई (i) नकारात्मक प्रावधान नहीं है और (ii) असंगतता है अन्य प्रावधानों के साथ. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, लागतों का पुरस्कार दिया जा सकता है दो उद्देश्यों के लिए हो, एक तो मुकदमेबाजी के खर्चों को पूरा करने के लिए और दूसरा, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या किसी मामले में न्याय करने के लिए और ऐसी परिस्थिति में, व्यय अनुकरणीय हो सकती है। ये सच है अधिकांश मामलों में उपरोक्त उद्देश्यों के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाना चाहिए उपयुक्त मामले और यह असीमित नहीं है बल्कि इसका प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।

अब, हम विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का उल्लेख करेंगे अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क देना कि व्यायाम करते समय लागत का भुगतान नहीं किया जा सकता है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार। रिलायंस है लासु जानू पवार और अन्य के निर्णय पर रखा गया। बनाम एम्परर, (1948) आकाशवाणी बॉम्बे 169, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि - जहां एक शिकायत और इसके परिणामस्वरूप होने वाली कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा दोनों के रूप में रद्द कर दिया जाता है यह तुच्छ और कष्टप्रद है, इसके पास इसके खिलाफ जुर्माना लगाने की कोई शक्ति नहीं है शिकायतकर्ता। उस उद्देश्य के लिए, न्यायालय ने संहिता के तहत उन धाराओं का उल्लेख किया जो विशेष रूप से कुछ प्रकार के मामलों में लागत या मुआवजा देने के लिए क्षेत्राधिकार/शक्ति प्रदान करते हैं और माना कि यह किसी के अस्तित्व को नकारात्मक बनाता है। अन्य मामलों में ऐसा करने की सामान्य शक्ति या क्षेत्राधिकार, जब तक कि ऐसी सामान्य शक्ति या क्षेत्राधिकार संहिता की धारा 56एल(ए) के परिणामस्वरूप न हो। इसके बाद न्यायालय ने माना कि यह धारा किसी भी अतिरिक्त शक्ति प्रदान किए बिना उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करने के लिए है और ए. टी. शंकर लिंग मुदलियार बनाम नारायण मुदा/ में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। आईएएस एवं अन्य, (1922) एआईआर मद्रास 502 द्वारा उक्त मामले में यह तर्क सही था। से अलग

होने से पहले फैसले में न्यायालय ने कहा कि इस पर विचार करना विधायिका का काम है निजी अभियोजकों द्वारा शुरू की गई आपराधिक शिकायत में व्यापक शक्तियां ऐसे मामलों में जहां शिकायत तुच्छ या परेशान करने वाली हो या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो, लागत देने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया जाना चाहिए। मामले में मद्रास हाई कोर्ट की फुल बेंच का फैसला ए. टी. शंकर लिंग मुदलियार (सुप्रा) ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या उच्च न्यायालय के पास किसी बरी किए जाने के खिलाफ क्राउन द्वारा नहीं बल्कि एक निजी अभियोजक द्वारा लाई गई पुनरीक्षण याचिका पर लागत देने की शक्ति थी, कौन सी याचिका फेल हो गई है. फैसला सुनाते हुए श्वाबे सीजे ने यह कहा यदि शक्ति हो तो यह एक ऐसा मामला है जिसमें वह सहर्ष लागत अनुदान देंगे। अदालत इसके बाद देखा गया कि चूंकि न्यायालय एक आपराधिक मामले में पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा था और संहिता कई मामलों में भुगतान का प्रावधान करती है व्यय और चूंकि ऐसे मामले में व्यय अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है "एक्सप्रेसियो यूनिस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरियस" [एक चीज़ की अभिव्यक्ति बहिष्करण बी है दूसरे का] लागू होता है और माना जाता है कि व्यय का भुगतान व्यायाम द्वारा नहीं किया जा सकता है अंतर्निहित शक्तियां. यह मानने से पहले कि न्यायालय को लागत अनुदान देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

किसी न्यायालय के पास लागत अनुदान देने की अंतर्निहित शक्ति हो सकती है। यह वेस्ट हैम यूनियन के संरक्षकों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक फैसले से स्पष्ट है सेंट मैथ्यू, बेथ्रल ग्रीन (1896) ऐप के बनाम चर्चवार्डेस आदि। कैस 477 जहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि उनके पास लागत देने की अंतर्निहित शक्ति है, और बॉम्बे सिविल फंड अधिनियम, 1882 में: प्रिंगल बनाम/एस भारत के राज्य सचिव (5) जहां कॉटन और बोवर, एल.जे.जे. राज्य स्पष्ट रूप से उनका विचार है कि उनके पास लागत अनुदान देने की अंतर्निहित शक्ति है मामला जो उनके सामने आया, हालांकि उन्हें व्यय अनुदान देने में सक्षम कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था। लेकिन, मेरे विचार में, उस अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग हमेशा यहीं तक सीमित और सीमित होना चाहिए कि यदि न्यायालय द्वारा व्यय अनुदान की शक्ति उस प्रकार की है कार्यवाही किसी तरह से क़ानून द्वारा प्रदान की जाती है, न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके, उन शक्तियों का विस्तार नहीं कर सकता है जो पहले थीं यह क़ानून द्वारा प्रदान किया गया है।

सहमति वाले फैसले में, कोर्ट ने जे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोर्ट ऑफ इक्विटी इंग्लैण्ड में इस तरह के अधिकार क्षेत्र पर अपना कब्ज़ा हमेशा और लगातार जताया जाता रहा इसका उपयोग करें जैसा कि

विभिन्न निर्णयों में बताया गया है कि यह व्यय तय कर सकता है। विद्वान न्यायाधीश ने गार्डियंस ऑफ वेस्टहैम यूनियन (सुप्रा) में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले का भी उल्लेख किया और कहा कि उक्त मामले में, निस्संदेह यह निर्धारित किया गया था कि देश में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में अपनी स्थिति के आधार पर और नहीं के न्यायालयों से शक्तियों के किसी भी हस्तांतरण द्वारा इक्विटी के पास व्यय से निपटने का अधिकार क्षेत्र था। हालाँकि, इसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने कहा "लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य कारण यह है कि इस न्यायालय के लिए तर्क की उस पंक्ति को अपनाना और पुरस्कार देने का दायित्व अपने ऊपर लेना संभव नहीं है। आपराधिक मामलों में mn~ns"; यह है: पुनरीक्षण एक अंतर्निहित शक्ति नहीं है यह या कोई अन्य न्यायालय: पुनरीक्षण की पूरी मशीनरी क़ानून का एक प्राणी है और इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की चार दीवारों के भीतर पाया जाना चाहिए और, जहां तक आपराधिक मामलों का संबंध है, मैं ऐसा करता हूं यह नहीं देखते कि हम पूरक बनने के लिए अपने अंदर अंतर्निहित शक्ति कैसे स्थापित कर सकते हैं लागतों को पुरस्कृत करके इसे पूरक करने की अंतर्निहित शक्ति को अपने ऊपर लेकर पूरी तरह से वैधानिक मशीनरी।"

पूर्वोक्त निर्णय को फिर से पी. वीरप्पा बनाम अवुदायम्मल और अन्य, एआईआर (1925) मद्रास 43 8 में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण

पीठ द्वारा अपनाया गया, जिसमें न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय के पास कोई शक्ति नहीं है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 और 148 के तहत पारित आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण की सुनवाई पर अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करें।

पूर्ण पीठ के उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि कोर्ट ने न देने के तीन कारण दर्ज किए। सबसे पहले, न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था। दूसरे, न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं कर सकता। तीसरा, न्यायालय ने कहावत "एक्सप्रेसियो यूनिस इस्ट एक्सक्लूसियो" पर भरोसा किया अल्टरियस" और यह माना गया कि चूंकि न्यायालय को अनुदान देने का अधिकार देने वाले विशिष्ट प्रावधान हैं, यह व्यय अनुदान देने की किसी भी अन्य शक्ति को बाहर करता है। हमारे विचार में, उपरोक्त कारण जांच के दायरे में नहीं आएंगे; सबसे पहले, क्योंकि नकारात्मक प्रावधान है कि मामलों को छोड़कर जिसके तहत प्रदान संहिता की विभिन्न धाराएँ, उच्च न्यायालय। व्यय अनुदान देने के अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसे मामलों में जहां कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय हासिल करने के लिए, न्यायालय को लगता है कि अनुकरणीय व्यय सहित व्ययो के लिए आदेश पारित करना आवश्यक है, तो वाक्यांश "ऐसे" आदेश" में वही शामिल होगा

और "ऐसी शक्ति" वाक्यांश के दायरे को प्रतिबंधित करने का कोई कारण नहीं है। दूसरे, अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के संबंध में डॉ. रघुवीर सरन (सुप्रा) के मामले में विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि "क़ानून यह नहीं कहता है कि मान्यता प्राप्त अंतर्निहित शक्ति केवल वैसी ही है जैसी अतीत में प्रयोग की गई है।" आगे यह देखा गया है कि उच्च न्यायालयों ने न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने की अंतर्निहित शक्ति जो असाधारण शक्तियों की प्रकृति में हैं जहां उच्च न्यायालय को कोई स्पष्ट शक्ति उपलब्ध नहीं है किसी विशेष कार्य को करना और जब उसकी व्यक्त शक्ति ऐसी अंतर्निहित शक्ति के अस्तित्व को नकारात्मक न कर दे। से यह और भी स्पष्ट हो जायेगा मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा संदर्भित अंग्रेजी निर्णय। बॉम्बे सिविल फंड अधिनियम, 1882 के संदर्भ में: प्रिंगल बनाम भारत के राज्य सचिव, (1889) चांसरी डिवीजन 288 अपील न्यायालय ने माना कि भले ही अधिनियम में एक सफल दावे की लागत देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन न्यायालय के पास अदालत को गलत तरीके से चालू करने की व्यय का भुगतान करने का आदेश देने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र था, और विधानमंडल को दिखाने के लिए अधिनियम में कुछ भी नहीं था इरादा था कि न्यायालय को ऐसा अधिकार क्षेत्र न मिले। न्यायालय में किए गए निरर्थक और अनुचित आवेदन के मामले में, न्यायालय को इसका सामान्य होना चाहिए यह कहने की शक्ति कि ऐसे आवेदन को जुर्माने सहित खारिज कर दिया जाना चाहिए।

"सच्चाई यह है, जैसा कि मुझे लगता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसा कि अपील की सर्वोच्च अदालत है और आवश्यक रूप से अंतर्निहित होना चाहिए लागत के संबंध में क्षेत्राधिकार कि यह अंतर्निहित क्षेत्राधिकार है मुझे लगता है कि अपील की लागत से निपटने में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कार्रवाई का अधिकार उस नवीनतम परिवर्तन से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है जो इस सदन ने उस मामले के संबंध में अपने व्यवहार में किया है। बहुत लंबे समय तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह प्रथा थी कि "अपने पक्ष में डिक्री का बचाव करने और उसे बनाए रखने के लिए आने वाली पार्टी के खिलाफ" कभी भी व्यय नहीं दी जाती थी: मैकर्सी बनाम रामसेज़। (1) इसे एक अन्य नियम कहा गया था। लेकिन 1877 में न्यायिक अधिनियम पारित होने के बाद उस नियम को बदल दिया गया। और इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अपने स्वयं के प्रस्ताव से, बिना किसी वैधानिक अधिकार के, केवल उस सिद्धांत पर बदल दिया था, जिसने तब इस सदन की सराहना की थी, कि एक सफल अपीलकर्ता क्षतिपूर्ति का हकदार था: बोवेस वी. शैंड (2), प्रति लॉर्ड केर्न्स एल.सी. और लॉर्ड ब्लैकबर्न।" ऐसा कोई कारण नहीं है उपरोक्त सिद्धांत का पालन करें।"

तीसरा, कहावत "एक्सप्रेसियो यूनिस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरियस" का अपना सीमित संचालन है। इसका संचालन उन अनुभागों के संबंध में प्रतिबंधित किया जाना है यह मानते हुए कि उन धाराओं में उल्लिखित मामलों के लिए, अदालत को कुछ मामलों में लागत अनुदान देने का अधिकार दिया गया है, अदालत व्यय देने के अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती है या उक्त धाराओं द्वारा प्रदान की गई विधि से अलग किसी विधि और मोड में व्यय देने का आदेश पारित नहीं कर सकती है। इस कहावत को लागू करने से असंगतता और अन्याय को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि मामलों में जहां न्यायालय ने पाया कि धारा 482 के तहत एक याचिका प्रक्रिया का दुरुपयोग है कानून और न्यायालय की कार्यवाही को खींचने सहित किसी गुप्त उद्देश्य के लिए एक अनुचित याचिका, यह कोई अन्य आदेश पारित कर सकता है, लेकिन आदेश नहीं लागत के लिए।

इसके अलावा, कहावत "एक्सप्रेसियो" के आधार पर व्याख्या के नियम के लिए यूनिस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरियस", डीन बनाम विसेनग्रंड, (1955) 2 क्यूबीडी 120 के मामले में रानी की बेंच द्वारा दिए

गए फैसले में इस पर विचार किया गया है। न्यायालय ने उक्त कहावत पर विचार किया और माना कि आखिरकार यह एक से अधिक है निर्माण के लिए सहायता और यदि संभव हो तो इसका वजन बहुत कम है "एक्सक्लूसियो अल्टरियस' को प्रभावित करने के इरादे के अलावा अन्य आधारों पर "इनक्लूसियो यूनियस" को ध्यान में रखें। इसके बाद, न्यायालय ने को/क्वून बनाम ब्रूक्स, (1887) 19 क्यूबीडी 400 एट 406 के मामले से निम्नलिखित अंश का उल्लेख किया जिसमें। न्यायालय ने अपनी मंजूरी के लिए कहा- "उद्धरण" 'एक्सप्रेसियो यूनिस इस्ट एक्सक्लूसियो एटेरियस' हम पर थोपा गया है। मैं कोर्ट में कही गई बातों से सहमत हूं। इस कहावत के बारे में विल्स जे द्वारा नीचे दिया गया है। यह अक्सर एक मूल्यवान नौकर होता है, लेकिन दस्तावेजों के क़ानून के निर्माण में पालन करने के लिए एक खतरनाक स्वामी होता है।बहिष्करण अक्सर असावधानी या दुर्घटना का परिणाम होता है, और कहावत यही होनी चाहिए लागू नहीं किया जाना चाहिए, जब इसका आवेदन उस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए जिस पर इसे लागू किया जाना है, असंगतता या अन्याय की ओर ले जाता है। मेरी राय में,इस कहावत को यहां लागू करने से असंगति और अन्याय को बढ़ावा मिलेगा, और 1920 के अधिनियम की धारा 14(.एल) को अनिश्चित और बना देगा इसका संचालन।"

उपरोक्त कहावत को इस न्यायालय द्वारा सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क बनाम राष्ट्रीय तंबाकू कंपनी, [1972] 2 एससीसी 560, के मामले में संदर्भित किया गया था। उस मामले में न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच करने की कोई निहित शक्ति थी या नहीं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम आईओ (ए) के साथ पढ़ा जाए और उपरोक्त अनुच्छेद का संदर्भ दिया जाए। कहावत "अक्सर एक मूल्यवान नौकर होता है, लेकिन एक खतरनाक स्वामी ..' और माना जाता है कि नियम उस मूल सिद्धांत के अधीन है जिसके लिए न्यायालयों को प्रयास करना चाहिए विधायी इरादे और उद्देश्य का पता लगाएं, और फिर निर्माण का एक नियम अपनाएं जो इन्हें विफल करने वाले के बजाय प्रभावी हो। इसके अतिरिक्त, आवश्यक निहितार्थ द्वारा निषेध का नियम केवल वहीं लागू किया जा सकता है जहां किसी कर्तव्य के पालन के लिए एक निर्दिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई हो। यदि परभणी ट्रांसपोर्ट को-ऑप सोसायटी लिमिटेड बनाम आर.टी.ए. औरंगाबाद, [1960] 3 एससीआर 177, इस न्यायालय ने देखा कि कहावत "एक्सप्रेसियो यूनिस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरियस" विधायिका के इरादे का पता लगाने के लिए एक कहावत है और कहां है वैधानिक भाषा सरल और अर्थ स्पष्ट है, लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा, हरीश चंदर वाजपेई बनाम त्रिलोकी सिंह, [1957] एससीआर 371 में, 389,

न्यायालय ने मैक्सवेल के निम्नलिखित अंश का उल्लेख किया क़ानून की व्याख्या, 10 वां संस्करण, पृष्ठ 316-317:-

> "प्रावधान कभी-कभी क़ानूनों में पाए जाते हैं, अपूर्ण रूप से या इसके लिए अधिनियमित होते हैं विशेष मामलों में केवल वह जो पहले से ही और अधिक व्यापक रूप से कानून था, कभी-कभी इस तर्क के लिए आधार प्रदान करता है कि एक इरादा है सामान्य कानून को बदलने के लिए, आंशिक या सीमित अधिनियमन से अनुमान लगाया जाना था, जो कि मैक्सिम एक्सप्रेसियो यूनिस, एक्सक्लूसियो अल्टरियस पर आधारित था। लेकिन वह मैक्सिम ऐसे मामलों में लागू नहीं होता है। एकमात्र निष्कर्ष जो एक अदालत ऐसे अनावश्यक प्रावधानों से निकाल सकती है (जो आम तौर पर निराधार आपत्तियों और निष्क्रिय संदेहों को पूरा करने के लिए अधिनियमों में जगह देती है), यह है कि विधायिका या तो कानून की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ थी या अनभिज्ञ थी, या उसने अतिरेक के प्रभाव में कार्य किया सावधानी।"

अंत में, हम यह बताएंगे कि पंपथी बनाम मैसूर राज्य के मामले में ·(सुप्रा), न्यायालय ने विशेष रूप से देखा है कि कोई विधायी अधिनियम नहीं है सभी मामलों के लिए प्रक्रिया प्रदान की

जानी चाहिए और न्यायालय को ऐसा करना चाहिए कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा अंतर्निहित शक्तियाँ हैं जो हैं कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक है। हमारे विचार में, धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की व्याख्या के लिए पूर्वोक्त कहावत का अनुप्रयोग केवल ऊपर बताए अनुसार सीमित संचालन होगा।

परिणाम में, हम मानते हैं कि अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए धारा 482 सीआर.पी.सी., न्यायालय के पास 'ऐसे आदेश' पारित करने की शक्ति है (असंगत नहीं)। संहिता का कोई भी प्रावधान उचित मामलों में लागत के आदेश सहित, (i) संहिता के तहत पारित किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या (iii) अन्यथा न्याय का अंत सुरक्षित करने के लिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस असाधारण शक्ति का उपयोग अपवादिक स्थिति में किया जाना हैपरिस्थितियों के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से। मुकदमेबाजी को पूरा करने में व्यय आ सकता है उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यय या अनुकरणीय हो सकते हैं।

उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज

नोटः यह अनुवाद ऑर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पवन कुमार शर्मा (और.जे.ऐसे.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।